विदेशों से भारतीयों की वापसी

1375. **श्री रणजीत सिंह :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विगत तीन वर्षों के दौरान, अर्थात, 1989 से, भारतीय मूल के नागरिकों को अनेक देशों से भारत वापस लौटना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से इन भारतीयों को वापस भारत लौटने पर बाध्य होना पड़ा है और उनके प्रत्यावर्तन के क्या कारण थे;

(ग) इस अवधि के दौरान इन देशों से अपनी मातृभूमि वापस आने वाले भारतीयों की संख्या कितनी है और क्या सरकार ने इन भारतीयों की विदेशों में छूटी संपत्ति के संबंध में संबद्ध सरकारों को कोई दावे प्रस्तुत किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन देशों से ये संपत्तियां वापस प्राप्त हो गई हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्द फलेरियो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) किस-किस देश से कितने-कितने भारतीय निर्वासित किए गए, इसकी सूचना विदेश स्थित भारतीय मिशनों से मंगाई गई है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

सरकार ने इन निर्वासित व्यक्तियों की सम्पत्ति के संबंध में, अगर उन्होंने को सम्पत्ति छोड़ी हो तो, सम्बद्ध सरकारों के समक्ष अभी कोई दावा पेश नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चकमा शरणार्थियों के मानवाधिकारों का हनन

1376. **श्री रणजीत सिंह :**
सरदार हरजीत सिंह हरेड़ :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अगस्त, 1991 के दैनिक टेलीग्राफ में "पैनल अलेजेज ह्यूमन राइट्स एब्यूजेज ऑन चकमास" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि चकमा पर्वतीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है;

(ग) क्या हाल ही में चकमा शरणार्थियों के प्रतिनिधियों ने उक्त रिपोर्ट को अपने ज्ञापन सहित सरकार को दिया था;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार को इन चकमा शरणार्थियों के आवास, भोजन, दवाइयों आदि पर प्रति वर्ष बड़ी भारी धनराशि खर्च करनी पड़ रही है;

(ङ) चकमा पर्वतीय क्षेत्र में व्याप्त स्थिति के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान की रिपोर्ट को तथा चकमा शरणार्थियों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने इन शरणार्थियों को बंगलादेश वापस बुलाने के लिए बंगलादेश सरकार से प्रभावी कार्यवाही करने के लिए दबाव डाला है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चट्टगांव पर्वतीय क्षेत्र आयोग ने मई, 1991 को अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि बंगलादेश में चकमाओं के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। चकमा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें उल्लिखित रिपोर्ट का जिक्र किया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) जहां तक भारत चकमा शरणार्थियों का सवाल है, सरकार ने उनकी शीघ्र बंगलादेश वापसी के प्रश्न को बंगलादेश की सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर बार बार उठाया है। बंगलादेश के विदेश मंत्री की हाल ही की भारत यात्रा के दौरान भी इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था। हमें आशा है कि बंगलादेश की सरकार ऐसे आवश्यक और प्रभावी कदम उठाएगी जिनसे शरणार्थियों में चटटगांव पहाड़ी क्षेत्रों में अपने घरों को स्वेच्छा से और शीघ्रातिशीघ्र वापस जाने का विश्वास पैदा हो।

Inclusion of roads into National Highways In Bihar

1377. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether a Master Plan formed by the Government of India in 1977 had recommended 6 Roads of Bihar for inclusion in the list of National Highways;

(b) whether National Development Council also has recommended incorporation of these roads as National Highways; and

(c) if so, reasons of non-implementing of the scheme thereof?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (c) The Government is not aware of any Master Plan formulated in 1977. Presumably the Member is referring to the National Transport Policy Committee (N.T.P.C.) set up in April, 1978 which submitted its Report in May, 1980 recommending 37 routes aggregating to 12,955 kms. for being declared as new National Highways, including six roads in Bihar. However, additions to the National Highway grid are being made only gradually keeping in view the availability of funds for the purpose in different Plan periods, requirements of the system as a whole and other priorities. While doing so due consideration is being given to the recommendations made by the N.T.P.C. as well as other suggestions for new National Highways received from various State Governments.

Operational efficiency of DTC in South Region

1378. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the details of Frequency, scheduled tribs and operational efficiency of different routes in the South Region of DTC since 1988 till date, routewise and monthwise;

(b) the extent of shortfall increase in frequency, such. trips and operational efficiency on the above routes, routewise during the above period alongwith the reasons therefor;

(c) the action taken in the above matters and with what results; and

(d) what further action Government propose to like in this regard?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a)